लोकसभा चुनाव : नई सरकार, ? नीति

डॉ0 विक्रम सिंह

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के 81.45 करोड़ योग्य मतदाताओं में से 55 करोड़ मतदाताओं ने 930000 मतदान केन्द्रों के जरिए सात अप्रैल से 12 मई के बीच नौ चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देश में नई सरकार चुनी। यह चुनाव अपने आप में विश्व के सबसे बड़े चुनाव हैं। पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर पाने के लिए चुनाव आयोग के साथ–साथ भारत की जनता भी बधाई की पात्र है। इस से पहले की हम चुनावी नतीजों पर बात करें, चुनावी प्रक्रिया पर बात की जानी चाहिए।

इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में लगभग 3426 करोड़ रूपए खर्च हुए, जो 2009 के 1483 करोड़ से 131 फीसदी अधिक है। पूरे विश्व में इस से अधिक चुनावी खर्च केवल अमरीका में होता है। यह विडम्बना है कि दोनों देशों में प्रति व्यक्ति आमदनी में करीब दस गुणा फर्क है, लेकिन दोनों देशों में चुनावी खर्चा लगभग एक जैसा है। इन बढ़े हुए खर्च को चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों से जोड़कर देखा जा रहा है। यह अलग बात है कि इतना खर्च करने के बाद भी 34 फीसदी मतदाताओं को घरों से निकाला नहीं जा सका। चुनाव प्रचार के दौरान भी राजनीतिक दलों ने खूब पैसा बहाया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के दौरान ही लगभग 260 करोड़ रूपए भारत की भ्रष्ट पुलिस ने पकड़ा है जिसकी अखबारों में खबरें छपी, इस से चुनावों में काले धन के प्रयोग का मात्र हल्का सा अनुमान लगाया जा सकता है।

चुनाव में 1687 राजनीतिक पार्टियों के कुल 8251 उम्मीदवारों ने लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई तथा कांग्रेस को एतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इतनी अधिक सीटें मिलने की आशा खुद भाजपा नेतृत्व ने नहीं की थी।

69 दिन की यह पूरी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प पर मनोरंजक थी। नए प्रारूप में इसी दौरान आईपीएल का टूर्नामेंट भी शुरू हुआ। चुनाव प्रचार व आईपीएल में कई समानताएं देखी गई। आईपीएल ने जिस तरह अत्यधिक धन व ग्लैमर ला दिया है, कुछ ऐसा ही योगदान इस बार के चुनाव प्रचार को लोकतंत्र के लिए रहा है। दोनों में सिर्फ एक फर्क था– आईपीएल में कोई एक टीम या खिलाड़ी नायक नहीं था, परन्तु चुनाव प्रचार तथा खबरों व विज्ञापनों में एक ही व्यक्ति को नायक के तौर पर पेश किया गया।

यह चुनाव भाजपा के सुनियोजित प्रचार व मीडिया –सोशल मीडिया सहित– प्रबंधन के लिए याद रहेगा। कांग्रेस की नव–उदारवादी नीतियों व पूंजीवादी भ्रष्टाचार से आहत मतदाताओं को भाजपा का प्रचार यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि उनके दुखों का अंत केवल मोदी जी ही कर सकते हैं। भाजपा 5000 करोड़ से अधिक पैसे खर्च करके गुजरात मॉडल जनता को बेचने में सफल रही। भले ही बाबा रामदेव अपने आप को किंग मेकर की संज्ञा दे रहे हों, पर असल बात तो यह है कि आरएसएस ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पूरे चुनाव प्रचार का भी एक तरह से केन्द्रीकरण हो गया था। राष्ट्रीय मुद्दों, प्रदेशों की समस्याएं, आर्थिक नीतियां, साम्प्रदायिकता का प्रश्न– इन सब को ताक पर रख कर केन्द्र में था नरेन्द्र मोदी बनाम राहुल गांधी, और भाजपा द्वारा यह जानबुझ कर किया गया। कांग्रेस के खिलाफ गुस्से का आलम यह था कि जिन राज्यों में कांग्रेस के विकल्प ऐसे क्षेत्रीय दल थे, जिनका रूख मोदी के प्रति ढुलमुल था, उनका प्रदर्शन चुनावों में बेहतर रहा है– मसलन तमिलनाडु में जसललिता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत। इस ध्रुवीकरण के चलते प्रगतिशील पार्टियों को बड़ा झटका लगा है।

कारण जो भी हो परन्तु भाजपा को जनता ने अपना समर्थन दिया जिसके लिए भाजपा बधाई की पात्र है। हालांकि चुनाव परिणामों ने भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को भी उजागर कर दिया है। कुल 31 फीसदी मत –17 करोड़ हासिल कर भाजपा की मोदी नेतृत्व में बनने वाली सबसे कम मतों की बहुमत सरकार बन गई है। 11 करोड़ मत पाकर कांग्रेस को 44 सीटें मिली व 2 करोड़ मत पाकर बसपा जैसी पार्टी संसद में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। यह लोकतंत्र की विडम्बना है या भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कि विपक्षी मतों के बटवारे का फायदा उठाकर तथाकथित अल्पमत वाला दल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार बनाते हैं। इससे चुनाव सुधार की जरूरत भी महसुस की जा रही है।

'नई संसद'

नई संसद में इस बार हमने सबसे अधिक करोड़पति सांसद भेजे हैं। करोड़पतियों की संख्या में सबसे ज्यादा करोड़पति गुजरात से आते हैं जिसके 26 सांसदों में से 21 सांसद करोड़पति हैं। यही हाल राज्यसभा की भी है, जहां 55 नए सांसदों में से 36 करोड़पति हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उम्मीदवारी के लिए सम्पदा एक महत्वपूर्ण योग्यता बन गई है, जिसके चलते बहुत सारे व्यवसायी राजनीति में आ रहे हैं या राजनीतिज्ञ व्यवसायी बन जा रहे हैं।

चुनाव से पहले युवाओं को सभी पार्टियों ने बहुत महत्व दिया। कई नेताओं ने अपने आप को युवाओं के नेता के तौर पर पेश कर दिया लेकिन इस संसद में 55 वर्ष से अधिक सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे सांसदों की संख्या 253 है जो प्रतिशत के हिसाब 47 फीसदी है। पिछली संसद में यह 43 फीसदी के आसपास थे। 40 वर्ष से कम उम्र के सांसदों की संख्या केवल 13 फीसदी है।

सांसदों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस बार लोकसभा में दसवीं पास सांसद 10 फीसदी हैं, जबकि 2009 में यह संख्या 20 फीसदी और 2004 में 19 फीसदी थी।ग्रेजुएट सांसदों की संख्या भी पहले से कम हुई है, 2004 में 43 फीसदी, 2009 में 44 फीसदी और 16वीं लोकसभा में 41 फीसदी सांसद ग्रेजुएट हैं। इस लोकसभा में 28 प्रतिशत सांसद स्नातकोत्तर, 2004 में यह संख्या 27 फीसदी और 2009 में 30 फीसदी थी। ऐसे सांसद जिन्होंने 10वीं भी पास नहीं की है उनकि संख्या पिछली बार के 3 फीसदी से बढ़कर 13 फीसदी हो गई है।

लगभग सभी सांसदों ने यह चुनाव राजनीति से अपराधीकरण व भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावों के साथ लड़े थे परन्तु हमारे 541 सांसदों में से 186 ऐसे हैं जो आपराधिक छवी के हैं यानि कि 36 फीसदी सांसद। इनमें से 112 तो ऐसे हैं जिन पर हत्या, हत्या के प्रयास, साम्प्रदायिकता, हिंसा, अपहरण और महिलाओं के ख्खिलाफ अपराध के आरोप हैं। साम्प्रदायिकता के आरोपों वाले सांसदों की संख्या 16 है जिस में 12 भाजपा के टिकट पर जीत कर आए हैं। 10 सांसदों पर चोरी औश्र डकैती के मामले चल रहे हैं, 7 भाजपा के हैं। इस तरह से देखें तो भाजपा के 281 सांसदों में से 35 फीसदी पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के 18 फीसदी, अन्नाद्रमुक के 16 फीसदी, शिवसेना के 83 फीसदी और तृणमूल कांग्रेस के 21 फीसदी सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उपरोक्त आपराधिक छवी वाले हमारे सांसद किस तरह से जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

नई सरकार के कुछ कदम :

नई सरकार के काम काज व नीतियों के बारे में अभी कुछ अनुमान लगाना गलत होगा व बहुत लोग इसे पूर्वाग्रह से ग्रसित समझेंगे। परन्तु माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के पहले कुछ निर्णय, उनकी आर्थिक नितियों और एजैण्डे की तरफफ इशारा करते हैं। मंत्रिमंडल का गठन ही मंत्रियों की शैक्षणिक योगयता पर विवाद से शुरू हुआ । मानव संसाधन विकास मंत्री व दिवंगत ग्रामीण विकास मंत्री र आरोप है कि उन्होंने नामजदी के पर्चे भरते समय स्वेच्छा से दायर किए गए हलफिया बयान में गलत जानकारी दी हैं। हालाकि हम शैक्षणिक स्तर को चुनाव लड़ने, जीतने

व मंत्री बनने में कोई बाधा नहीं समझते हैं क्योंकि हमारे देश में 'एक व्यक्ति एक वोट' तथा 'एक वोट एक मूल्य' का सिद्धांत अपनाया गया है। परन्तु पूरे चुनाव में सुशासन की दुहाई देने वाले मोदी के मंत्रियों यह धोखाधड़ी समझ से परे है। सच स्वीकारने के बजाय सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उन पांच कर्मचारियों को ही निलम्बित कर दिया, जिन्होंने मीडिया के पूछने पर सही जानकारी दी थी।

यूपीए सरकार के दौरान व चुनाव प्रचार में भाजपा नव–उदारवादी नीतियों पर घरियाली आंसू बहाती रही व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कोसती रही, परन्तु सत्ता में आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि ताकतवर व लौह पुरूष मोदी जी ने उन्हीं नीतियों पर एक्सीलेटर को मजबूती से दबा दिया है।

डीजल व पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि की छूट को भाजपा सरकार की जनता को पहली भेंट थी। वे लोग जिन्होंने भाजपा को नव–उदारवादी नीतियों के विकल्प के तौर पर चुना था तथा अभी मोदी जी की जीत की खुशी मना रहे थे, रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने उनके सपनों को तोड़ दिया। गौरतलब है कि स्वदेशी आंदोलन की ठेकेदार समझे जानी वाले आरएसएस ने भी इसका पूरा समर्थन किया । देश की जनता ने भाजपा को अपने रोज की मुसीबतों को दूर करने के लिए चुना जो गरीबी व महंगाई से त्रस्त है। परन्तु सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों को संविधान की धारा 370 की याद आ जाती है और यही सरकार चुने जाने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है। यह प्राथमिकता किस तरफ इशारा कर रही है, जनता को इसका आभाष होने लगा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने तो 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा ही बदलने की बात कह दी। इनके अनुसार– '' मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है बलिक पारसी हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं''। माननीय मंत्री जी की विचारधारा उन पर इस कदर हावी हो गई ि कवह यह भी भूल गई कि अल्पसंख्यक एक्ट के राष्ट्रीय आयोग ने 1992 में अधिसूचना जारी करके भारत में मुसलमान, इसाई, सिख, बौद्ध व पारसी समुदायों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया था।

सभी कार्यक्रमों में मोदी जी अगले दस साल की योजना बनाने की बात कर रहे हैं, परन्तु उनकी सरकार के पहले कुछ दिनों ने ही बहुत गंभीर संकेत दिए हैं। भाजपा ने यूपीए की आर्थि नीतियों को ही आगे बढ़ाने की मंशा स्पष्ट कर दी है और साफ है कि जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है।वैसे भी भाजपा की टिकट से चुने गए सांसदों में से 100 से अधिक सांसद पहले कांग्रेस में ही थे। अब तो हम यह भी नहीं कह सकते कि चेहरे बदल गए पर नीतियां वही हैं क्योंकि कुछ –कुछ चेहरे भी वही हैं।

पूरे देश को गुजरात बनाने का दावा करने वाले मोदी जी ने जिस तरह नई सरकार में सत्ता के केन्द्र को अपने पास ही रखा है, उस से सही मायने में उनके गुजरात वाले चेहरे की ही झलक आ रही है।